शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 37 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 8 – 15 सितम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक का निदेशक मण्डल भंग किये जाने की पृष्ठभूमि में बैंस की शिकायत है

शिमला/शैल। रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला के निदेशक मण्डल को भंग करके वहां पर प्रशासक बैठा दिया है। बैंक के निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर जवाब तलब किया है। बैंक पर आरोप है कि उसने आर.बी.आई. और नाबार्ड के दिशा निर्देशों की अवहेलना करके बैंक को नुकसान पहुंचा है। कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है। जिसके प्रशासन और नीतियों में सरकार का बड़ा दखल रहता है। इस नाते निदेशक मण्डल को भंग किये जाने की कारवाई बैंक के साथ सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाती है। स्मरणीय है कि नोटबंदी के दौरान पुराने नोटों को नयों के साथ बदलने के मामले में यह बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। बैंक लोगों की जमा पूंजी और कर्ज लेने देने का ही काम करता है। इस नाते बैंक पर लगने वाले आरोपों का दायरा भी यह कर्ज देने और वसूली करने में नाबार्ड और आर.बी.आई. के निर्देशों की अवहेलना तक जा पहुंचता है। बैंक ने किसको पात्रता के मानदण्डों की अवहेलना करके कितना कर्ज दे दिया और वसूली के नाम पर ओ.टी.एस. की आड़ में किसका कितना कर्ज माफ कर दिया यह सामान्य तौर पर बैंक पर उठने वाले सवाल रहते हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता युद्ध चन्द बैंस के प्रकरण में इस बैंक की कार्य प्रणाली सवालों में आयी थी। बैंस ने यहां तक आरोप लगाये थे की जमीन को कुछ दिल्ली स्थित राजनेताओं को देने की बैंक के माध्यम से योजना बनाई जा रही है। बैंस ने एक पत्रकार वार्ता में ऊना में खुलासा किया था कि वह ई.डी में शिकायतकर्ता है और उसकी शिकायत पर नादौन हमीरपुर में कारवाई हुई और आरोपी ई.डी. की डासना जेल तक पहुंचे। इस खुलासे के बाद विजिलैन्स ने बैंस के खिलाफ ऋण मामले के आरोपों पर मामला दर्ज कर लिया। यह मामला जब उच्च न्यायालय पहुंचा तो अदालत ने विजिलैन्स के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि विजिलैन्स ने बैंक के निदेशक मण्डल या किसी अधिकारी से कोई पूछताछ ही नहीं करी।

बैंस को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा तक प्रदान कर दी। बैंस प्रकरण में बैंक की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं। अभी तक बैंस प्रकरण अपनी चाल से चल रहा है। इस प्रकरण के बाद ही आर.बी.आई. और नाबार्ड की यह कारवाई सामने आयी है। यदि सूत्रों की माने तो सी.बी.आई. भी इस प्रकरण में सक्रिय हो गयी है और मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक जा पहुंचा है। बल्कि इसी दौरान इस बैंक के ओ.टी.एस. के और भी कुछ प्रकरण सामने आये हैं जो बैंक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हैं। इस बैंक के निदेशक मण्डल के खिलाफ हुई इस कारवाई की पृष्ठभूमि में बैंस को शिकायतों को एक बड़ा आधार माना जा रहा है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ के सी.बी.आई. कार्यालय में इसी माह बैंस की अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई है। इसी चर्चा के बाद बैंस प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा है। इसके बाद ही नाबार्ड और रिजर्व बैंक की यह कारवाई सामने आयी है।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन के कारण बाढ़ की स्थिति और नुकसान की समीक्षा के लिये 9 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश का दौरा किया।

प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के चंबा, भरमौर, कांगड़ा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक की जिसमें राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए मिनी किट भी जारी किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हाल ही में आई बाढ़ और भू-स्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे उनका दीर्घकालिक कल्याण सुनिश्चित होगा।

कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्षतिग्रस्त घरों की जियोटैगिंग की जाएगी। इससे नुकसान का सटीक आकलन करने और प्रभावित लोगों तक त्वरित गति से सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी।

निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल क्षति की रिपोर्ट करने और उसे जियोटैग करने में सक्षम होंगे, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता मिल सकेगी।

वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण के लिए जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन प्रयासों से भूजल स्तर में सुधार होगा और बेहतर जल प्रबंधन को बल मिलेगा।

केंद्र सरकार ने नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पहले ही भेज दिये हैं, तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने आपदा से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना और गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन नियमों के तहत राज्यों को

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने डलहौजी में आपदा प्रभावित लोगों को वितरित की खाद्य एवं राहत सामग्री

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ज़िला चम्बा के उप-मंडल डलहौज़ी के तहत बनीखेत

नगर पंचायत के सभागार में आपदा प्रभावित लोगों को खाद्य एवं राहत सामग्री वितरित की। राज्यपाल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज़ से संवेदनशील हो रहा है।

शिव प्रताप शुक्ल ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वर्ष 2023 के बाद से प्रदेश में आपदाओं की आवृत्ति बढ़ी है। इससे न केवल जन-धन की हानि हुई है बल्कि विकास कार्य भी प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हिमाचल दौरे के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य सरकार को 1500 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित जिलों का दौरा करने के पश्चात केंद्रीय मंत्रियों तथा अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल द्वारा किए गए आकलन के आधार पर प्रदेश को अतिरिक्त राहत राशि देने का आश्वासन भी प्रधानमंत्री ने दिया है।

शुक्ल ने प्रदेश को खाद्य एवं राहत सामग्री भेजने के लिए केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र में परिस्थितियों के लिहाज से अतिरिक्त खाद्य एवं राहत सामग्री की मांग के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों को सचिव राज्यपाल एवं राज्य रेडक्रॉस तथा उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रेडक्रॉस के कार्यालय में सूची प्रेषित करने को कहा।

राज्यपाल ने आपदा के दौरान प्रदेशवासियों के मनोबल और साहस की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने धैर्य, साहस और एकजुटता से विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिला में आगामी दो-तीन माह की समयावधि में सभी व्यवस्थाएं सामान्य होंगी।

उन्होंने इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर विधायक विपिन परमार, डॉ. हंसराज तथा डीएस ठाकुर ने भी अपने विचार साझा किए।

हिमाचली डॉक्टर को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के राशील गांव के लैप्रोस्कोपी डॉक्टर बाईकिंग भानू को जनजातीय क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी

मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर से जनजातीय क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने बाले जिन जनजातीय गण मान्य व्यक्तियों को राष्ट्रपति भवन में आमन्त्रित किया गया है उनमें हिमाचल से डॉक्टर बाईकिंग भानू एक मात्र प्रख्यात विद्वान हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जन जातीय क्षेत्रों की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण और कार्यन्वन के लिए अपने सुझाव देने के लिए आमन्त्रित किया गया।

उन्होंने 18 मई 2004 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवेरेस्ट पर विजय प्राप्त कर माउंट एवेरेस्ट पर विजय पाने वाले वह विश्व के पहले डॉक्टर बने। इसके लिये राष्ट्रपति ने उन्हें नौ सेना शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया।

उनका लक्ष्य राज्य के ग्रामीण, दुर्गम और जन जातीय क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है ताकि लोगों को घर द्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवायी जा सकें। वह दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले सर्जन को लप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन करने की नवीनतम तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और इसके लिए उन्होंने लप्रोस्कोपी लैंसर्स नाम का एक ग्रुप गठित किया है।

वह भानू अस्पताल कुल्लू और मण्डी के संस्थापक निदेशक हैं और इसके अतिरिक्त बह जन जातीय क्षेत्रों में मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं।

हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क, ऊना को पर्यावरणीय मंजूरी मिली

शिमला/शैल। ऊना में स्थापित होने जा रहे बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंज़ूरी मिल गई है। इस स्वीकृति से फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक इस पार्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिसका उद्देश्य अन्य देशों से सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक व प्रमुख कच्चे माल की निर्भरता को कम करना है। इस परियोजना को भारत सरकार से 996.45 करोड़ रुपये और राज्य सरकार से 1,074.55 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। परियोजना में 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता है और इससे 15,000 से 20,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक एसपीवी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो राज्य उद्योग विभाग के तत्वावधान में काम कर रही है। जनवरी 2025 में ईएसी की बैठक में इस परियोजना पर विचार किया गया था, जिसमें साइट निरीक्षण के लिए ईएसी की एक उप-समिति का गठन किया गया था। ईएसी के परामर्श के अनुसार, जल निकासी पैटर्न, विकास योजना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम गड़बड़ी, भूकंपीय भेद्यता, जोखिम मूल्यांकन, उप-सतही विरूपण और भूस्खलन आदि से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट एनआईटी हमीरपुर से तैयार की गई।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क भारत में दवा निर्माण के एक अग्रणी केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा और हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पर्यावरणीय मंजूरी ने विकास के अगले चरणों को तेजी से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह पार्क फार्मा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उद्योग विभाग के निदेशक आर. डॉ. नजीम ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरणीय मंजूरी मिलने का स्वागत करती है और इसे समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस ने कहा कि विभाग इस पार्क को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि एपीआई/केएसएम की निर्भरता कम की जा सके। उन्होंने कहा कि इस पार्क का विकास औषधि विभाग द्वारा बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के दिशा-निर्देशों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुपालन में किया जाएगा।

फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के अध्यक्ष बीआर सीकरी ने मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और परियोजना पर काम करने वाली पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ड्रग पार्क एक मजबूत और टिकाऊ फार्मा इको-सिस्टम का मार्ग प्रशस्त करेगा।

राज्यपाल ने चंबा उप-मंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा उपमंडल के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने

इस दौरान प्रभावितों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने ग्राम पंचायत करियां में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के भू-स्वलन प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कलसूंई तथा घरवाला में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय उच्च मार्ग और लोथल घार का भी जायजा लिया।

शुक्ल ने घरवाला के समीप ऐतिहासिक धार्मिक स्थल त्रिलोचन महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की।

उपायुक्त चंबा ने इस दौरान राज्यपाल को आपदा से हुई क्षति एवं व्यवस्था बहाली को लेकर जिला प्रशासन द्वारा उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

स्कूली पाठयक्रम में हिमाचल का इतिहास किया जाएगा शामिल:शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूली पाठयक्रम में संशोधन पर विचार-विमर्श के लिये एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पाठयक्रम में हिमाचल प्रदेश के समृद्ध इतिहास, साहित्य, संस्कृति और कला को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा पाठयक्रम तैयार करने के निर्देश दिए जिसमें राज्य के प्राचीन मंदिर, मठ, किले, ऐतिहासिक स्थल, पारंपरिक वास्तुकला, बोलियां, लोक कलाएं, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार और ऐतिहासिक आन्दोलनों को शामिल किया जा सके। उन्होंने हिमाचल के संदर्भों को शामिल कर छठी से बारहवीं कक्षा तक की एनसीईआरटी की पाठय पुस्तकों को प्रासंगिक बनाने को कहा ताकि बच्चों में प्रदेश के प्रति गर्व और अपनेपन की भावना विकसित की जा सके।

उन्होंने जनरल ज़ोरावर सिंह, वज़ीर राम सिंह पठानिया, डॉ. वाई.एस. परमार जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और कैप्टन विक्रम बतरा, मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन सौरभ कालिया जैसे शहीदों की वीरगाथाओं से बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगाने पर बल दिया। इस तरह के समावेश से छात्रों का राज्य के साथ जुड़ाव मज़बूत होगा और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी।

शिक्षा मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और सतत विकास जैसे समसामयिक मुद्दों को भी पाठयक्रमों शामिल किया जाये। आपदा प्रबधंन से जुड़ी शिक्षा व्यावहारिक और गतिविधि-आधारित होनी चाहिए ताकि बच्चे वास्तविक जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

उन्होंने कहा कि पाठयक्रम को बढ़ाने के बजाये उसे रूचिकर बनाया जाये। उन्होंने कार्यशालाओं, क्षेत्रीय भ्रमण, दृश्य सामग्री और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। उन्होंने स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर भी बल दिया।

रोहित ठाकुर ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी को निर्देश दिया कि वह अपनी वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के उपलब्ध शिक्षण सामग्री तक आसान पहुंच के लिए क्यूआर कोड और डिजिटल लिंक के साथ प्रदान करे।

बैठक के दौरान संशोधित पाठयक्रम तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। अधिसूचना के पश्चात यह समिति हिमाचल के संदर्भ में एनसीईआरटी की पाठय पुस्तकों की समीक्षा तथा आवश्यक संशोधन करेगी। समिति समग्र व स्थानीय रूप से प्रासंगिक शिक्षा के लिए पूरक सामग्री तैयार करेगी।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने अपने विचार साझा किए।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत के. शर्मा, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

आपातकाल स्थिति में लाभार्थियों को समयबद्ध राशन उपलब्ध करवाया:डॉ.एस.पी.कत्याल

शिमला/शैल। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल ने शिमला में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2019 के तहत लाभार्थियों के अधिकारों की प्रभावी समीक्षा और निगरानी के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री पोषण, एकीकृत बाल विकास योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

अध्यक्ष ने प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के दृष्टिगत आपात स्थितियों के दौरान अधिकारियों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर लाभार्थियों को समयबद्ध राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसी भी लाभार्थी को परेशानी का सामना न करना पड़े।

डॉ.एस.पी.कत्याल ने आयोग की शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए संबंधित विभागों को उचित मूल्यों की दुकानों तथा विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे लोगों को आयोग से सम्पर्क करने में सहायता मिलेगी।

बैठक के दौरान विभागीय प्रतिनिधियों ने आयोग को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में आयोग के सदस्य हेमिस नेगी, हितेश आजाद एवं सदस्य सचिव योगेश चौहान, विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन करने

के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके उपरांत उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री को इस मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को प्रदेश के सीमित संसाधनों से हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। लेकिन प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

सुक्खू ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत छूट प्रदान करने का आग्रह किया ताकि विस्थापित परिवारों को वन भूमि पर बसाया जा सके। उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्र से दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति देने का आग्रह किया।

आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सरकार की परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त सहायता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्तमान मापदंडों में संशोधन पर बल देते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के सुधार कार्यों में नई परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की तुलना में अधिक व्यय होता है। अभी तक राज्य सरकार को बहुत कम और विलंब से सहायता मिल रही है। बाढ़ की स्थिति में महीनों तक बंद रहने वाली राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान फ्रेक वर्क में इस प्रकार की क्षति का आकलन नहीं किया जाता है। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने राज्य की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने जलविद्युत उत्पादन से मुफ्त रॉयलिटी की मांग, 40 वर्षों के उपरांत केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व वाली बिजली परियोजनाओं को राज्य को हस्तांतरित करने की हिमाचल की मांग को भी दोहराया। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत ऑल वेदर सुरंगों के निर्माण और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में संपर्क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक पर्वतीय मार्गों के विकास के लिए भी केंद्र से सहयोग का आग्रह किया। कुल्लू से मनाली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत महत्त्वपूर्ण भूभूजोत सुरंग परियोजना संबंधी मामला भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा।

हिमाचल के हितों में सहयोग के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाएं पंजाब व हरियाणा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को कई मामलों पर अपने हकों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित शानन जलविद्युत परियोजना की लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद इसे पंजाब से हिमाचल को वापिस नहीं सौंपा गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी पंजाब और हरियाणा के अवरोध के कारण बीबीएमबी से बकाया राशि का भुगतान भी लंबित है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हमारे बड़े भाई की तरह हैं और उन्हें अपने छोटे भाई को उदार सहयोग प्रदान करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने शिमला में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के समापन सत्र में अपने संबोधन के दौरान यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया तथा बैंक के सहकारी गान और एक स्मारिका का विमोचन भी किया।

इस सत्र के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में सहकारी आंदोलन वर्ष 1904 में शुरू हुआ था और वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। वर्तमान में, राज्य में 5,000 से अधिक सक्रिय सहकारी समितियां हैं, जिनमें लगभग 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं। ये ऋण समितियां किसानों और ग्रामीण परिवारों को आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार सहकारी समितियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जमीन खरीदने के लिए धारा 118 के तहत छूट प्रदान करने पर विचार करेगी। उन्होंने राज्य सहकारी बैंक से छोटे किसानों, बागवानों, कामगारों और व्यापारियों को ऋण मुक्त बनाने में मदद के लिए वन टाईम सेटलमेंट पॉलिसी लागू करने को भी कहा।

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हिमाचल प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करने पर बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र की पहल पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 'सहकार टैक्सी सेवा' शुरू की है, जिससे हिमाचल के लोग लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हिमाचल के संस्थानों को नव स्थापित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष शुल्क रियायतों पर विचार करेगा।

उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड में 10 लाख से ज्यादा किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण मिला है। राज्य का लक्ष्य 15 लाख लोगों को इस आंदोलन से जोड़ना है, जिससे महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।

विक्रमादित्य ने केरल अर्बन कॉन्कलेव कोच्चि में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केरल अर्बन कॉन्कलेव कोच्चि में

भाग लिया। इस अवसर पर केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केरल के मुख्यमंत्री पिणराई विजयन भी उपस्थित थे।

उन्होंने इस अवसर पर शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी परिस्थितयों के अनुरूप जलवायु संवदेशील शहरी विकास मॉडल साझा करते हुए अन्य राज्यों के साथ अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने इस अवसर पर राज्यों के बीच आपसी सहयोग एवं सतत विकास को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया।

लोक निर्माण मंत्री ने 'कल के पहाड़' विजन के तहत जलवायु संवेदनशील शहरी विकास की व्यापक योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने शहरीकरण की तेज रफ्तार और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास और संरक्षण को संतुलित करने का संकल्प लिया है।

उन्होंने बताया कि पिछले 100 वर्षों में औसत तापमान में हुई 1.6 सेल्सियस वृद्धि और वर्ष 2023 व 2025 की अतिवृष्टि जैसी आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि जलवायु अनुकूलन अति अनिवार्य है। प्रदेश ने इस दिशा में कार्य करते हुए क्लाइमेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क, ढलानों की जैव इंजीनियरिंग से सुरक्षा, वर्षा जल संचयन झरनों का पुर्नजीवन और आधुनिक जल प्रबंधन जैसे कदम उठाए हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश ने 5 हजार करोड़ रुपये का हिमाचल ग्रीन डवेल्पमेंट फंड, कार्बन क्रेडिट से वार्षिक आय और पर्यटन आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जैसी नवाचार पूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। अक्षय ऊर्जा में 2400 मेगावाट क्षमता स्थापित कर हिमाचल शत-प्रतिशत नवीकरणीय बिजली उत्पन्न करने वाला पहला राज्य बना है।

उन्होंने कहा कि राज्य ने डिजिटल तकनीक से स्मार्ट सिटी प्रबंधन, कचरा पुनर्चक्रण, इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन और केवल कार जैसी पहलों ने शहरी जीवन को और अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया है। राज्य सरकार मंदिरों, वनों और पारम्परिक शिल्प कला को संरक्षित करते हुए प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की पहचान को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का वर्ष 2040 तक हिमाचल को क्लाइमेट-पॉजिटिव राज्य बनाने का लक्ष्य है ताकि इसे वर्ष 2047 तक विश्व का अग्रणी पर्वतीय विकास म डल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमालय हमें धैर्य और संतुलन की सीख देता है और इन्ही मूल्यों के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और जलवायु सवेदनशील हिमाचल का निर्माण संभव हो पाएगा।

प्रदेश में 98 प्रतिशत जलापूर्ति योजनाएं बहाल: उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश की 12007 जलापूर्ति योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है। यह कुल प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं का लगभग 98 प्रतिशत है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी दिन-रात फील्ड में रहकर प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को राहत पहुंचा रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं की बहाली में जुटे हुए हैं।

भारी बारिश के कारण प्रदेश में कुल 12281 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं इनमें से 12007 योजनाओं को क्रियाशील किया है। प्रदेश में जलापूर्ति योजनाओं को लगभग 925.85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 244.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 2624 सिंचाई योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। राज्य में स्थापित 115 बाढ़ सुरक्षा कार्यों को 55.81 करोड़ रुपये, 183 सीवरेज योजनाओं का 64.33 करोड़ रुपये तथा 391 हैंडपंपों को 1.20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 15594 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इन योजनाओं को कुल 1291.37 करोड़ रुपये की अनुमानित क्षति आंकी गई है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि बहाली के कार्यों में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाये। सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और सभी प्रभावित योजनाओं को शीघ्र स्थायी रूप से बहाल किया जाएगा।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 में परवाणु शहर को देश में मिला दूसरा स्थान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के परवाणु शहर ने प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड से सम्मानित किया।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि यह सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत करवाया गया था। देश के तीन लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में परवाणु शहर को देश के स्वच्छ वायु शहरों में दूसरे

स्थान पर आंका गया है। इस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को 25 लाख रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में नवाचार पहल के लिए प्रेरित करेगी।

उप-मुख्य सचेत ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री से शाहपुर में शहीद स्मारक स्वीकृत करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने वीरवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने शाहपुर विधानसभ क्षेत्र में शहीद समारक को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि शाहपुर के सुबेदार पवन सिंह जरियाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले क्षेत्र के पहले सैनिक थे। उनकी शहादत की स्मृति में शाहपुर में शहीद समारक बनाने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार ने इसके लिए पहले ही क्षेत्र में भूमि चिन्हित व आबटित कर दी है और रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति मिलने पर शीघ्र समारक का निर्माण हो पाएगा।

प्रदेश सरकार ने 00-24-00 हैक्टेयर भूमि भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी है ताकि शाहपुर में टाइप-सी इसीएचएस पॉलिक्लिीनिक, एक सीएसडी कैनटीन और एक सैनिक विश्राम गृह का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि अब तक इन परियोजनाओं के लिए रक्षा मंत्रालय से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

थोड़ा सा अभ्यास ढेर सारे उपदेशों से अधिक मूल्यवान है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद उभरते राजनीतिक सवाल

उपराष्ट्रपति के चुनाव में एन.डी.ए. के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन को बड़ी जीत हुई उन्हें इण्डिया गठबंधन के उम्मीदवार के मुकाबले 452 मत मिले हैं जबकि इण्डिया गठबंधन के जस्टिस रेड्डी को 300 मत मिले हैं। इस चुनाव में पन्द्रह मत अवैध पाये गये हैं और तेरह सांसदों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। एन.डी.ए. के उम्मीदवार की जीत को गृह मंत्री अमित शाह के कुशल राजनीतिक प्रबंधन का कमाल मान जा रहा है। गृह मंत्री के पास ई.डी. और सी.बी.आई. जैसे हथियार हैं और इन हथियारों का भी परोक्ष/अपरोक्ष में इस्तेमाल होने की चर्चाएं भी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से उठ खड़ी हुई हैं। इन चर्चाओं को इसलिये अधिमान देना पड़ रहा है क्योंकि देश की राजनीति में इन हथियारों का इस्तेमाल 2014 के चुनावों के बाद से एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। उपराष्ट्रपति का यह चुनाव जिस तरह के राजनीतिक वातावरण में हुआ है उसमें इन चर्चाओं को नकारा भी नहीं जा सकता। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर एक लंबे अरसे से सवाल उठते आ रहे हैं। आज यह सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रमाणिक खुलासे के बाद ''वोट चोरी'' के एक बड़े अभियान तक पहुंच गये हैं। बिहार में एस.आई.आर को लेकर चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय में बहस जिस मोड़ तक जा पहुंची है वह अपने में ही बहुत कुछ कह जाती है।

इस पृष्ठभूमि में उपराष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े अपने में बहुत बड़ी बहस को अंजाम दे जाते हैं। इण्डिया गठबंधन की एकता पर पहला सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस चुनाव का परिणाम आने से पहले ही यह दावा किया था कि इण्डिया ब्लॉक के सभी तीन सौ पन्द्रह सांसदों ने मतदान किया है। परिणाम आने पर इंडिया ब्लॉक को तीन सौ वोट मिले पन्द्रह वोट अवैध घोषित हुये। इन अवैध मतों पर चर्चा कांग्रेस नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी के ब्यानों के बाद ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसी कड़ी में तेरह सांसदों का मतदान में भाग ही न लेना और भी गंभीर सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि मतदान से पहले किसी भी सांसद ने उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों को लेकर कुछ नहीं कहा था। जबकि इस चुनाव में कोई भी दल अपने सांसदों को सचेतक जारी नहीं किये हुये था। क्योंकि इसका प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आज भी हमारे सांसद राष्ट्रीय महत्व के राजनीतिक प्रश्नों पर अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं। इसी के साथ पन्द्रह सांसदों के मतों का अवैध पाया जाना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे सांसदों को वोट डालना ही नहीं आता है या यह एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। इस पर आने वाले दिनों में खुलासे आने की संभावना है।

जिन राजनीतिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चुनाव आया और मतदान हुआ उससे यह स्पष्ट हो गया है कि ''वोट चोरी'' के जनान्दोलन में सरकार के लिये स्थितियां सहज नहीं रही हैं। यदि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा का आंकड़ा दो सौ चालीस पर आकर रुक सकता है तो निश्चित तौर पर वोट चोरी के आरोप का प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। क्योंकि यह इसी आरोप का प्रतिफल है कि भाजपा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना कठिन होता जा रहा है। इसी आरोप के कारण प्रधानमंत्री का पच्चहत्तर वर्ष की आयु सीमा का सिद्धांत भी अभी अमल से दूर रखना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में इण्डिया गठबंधन को कमजोर करने के लिये नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को अक्षम प्रमाणित करने के लिये कांग्रेस की राज्य सरकारों को अस्थिर करके उन्हें भाजपा में शामिल होने की परिस्थितियों बनाई जा सकती हैं। जब राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर भाजपा के स्लीपर सैल होने की बात की थी उसके बाद कांग्रेस के भीतर भी असहजता की स्थिति पैदा हुई है। हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार ने जब राहुल गांधी पर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप लगाया तो प्रदेश के एक भी कांग्रेस नेता ने इसका जवाब नहीं दिया। क्या इसे महज एक संयोग माना जा सकता है या यह एक प्रयोग था।

भारत की डिजिटल क्रांति:परिवर्तन का एक दशक और भावी योजना

राव इंद्रजीत सिंह
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

पिछले एक दशक में भारत में एक ऐसी डिजिटल क्रांति आयी है जो असाधारण है। जो प्रक्रिया लक्षित प्रौद्योगिकीय अंत:क्षेपों की एक श्रृंखला के रूप में शुरू हुई थी वह अब एक व्यापक परिवर्तन के रूप में विकसित हो चुकी है, जो भारतीय जीवन के लगभग हर पहलू जैसे अर्थव्यवस्था, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वाणिज्य, और देश के कोने-कोने में बसे किसानों और छोटे उद्यमियों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है।

यह यात्रा आकस्मिक नहीं थी। इसे भारत सरकार द्वारा ठोस नीति निर्धारण, अंतरमंत्रालयी सहयोग, और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया गया है। जब संबद्ध मंत्रालयों जैसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), कृषि मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयों ने बड़े पैमाने में ज़मीनी स्तर पर परियोजनाओं को पूरा किया, तो दूसरी ओर नीति आयोग ने अभिसरण को बढ़ावा देकर, विचारों को नेतृत्व देकर, और स्केलेबल, नागरिक-प्रमुखता वाले नवाचारों की ओर प्रणाली को प्रेरित कर नीति इंजन का काम किया है।

जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी की शुरुआत के साथ इसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। लगभग 55 करोड़ बैंक खातों के खोलने के साथ-साथ, करोड़ों लोगों को, जो पहले वित्तीय प्रणाली की पहुंच से बाहर थे, उन्हें अकस्मात बैंकिंग व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक पहुंच प्राप्त हुई है।

ओडिशा के एक छोटे से गांव में पहली बार बिना बिचौलिए की सहायता से एक सिंगल मदर को कल्याणकारी लाभ सीधे उनके खाते में प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया। उनकी कहानी भारत भर के करोड़ों लोगों की कहानी बन गई है। यह वृहद वित्तीय समावेशन आंदोलन वित्त मंत्रलय के समर्थन और आधार तथा मोबाइल पैठ की सक्षम सहायता से अगला कदम: एक वित्तीय-प्रौद्योगिकी विस्फोट का आधार बना।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) ने भारतीयों के लेन-देन के तरीके में क्रांति ला दी है। किसी मित्र को पैसे भेजने के एक अनूठे तरीके के रूप में शुरू किया गया यह तरीका शीघ्र ही छोटे व्यवसायों, सब्ज़ी विक्रेताओं और गिग वर्कर्स की जीवनरेखा बन गया। आज, भारत में प्रति माह 17 बिलियन से अधिक यूपीआई के माध्यम से लेनदेन होते हैं, और यहां तक कि सड़क किनारे के विक्रेता वाले भी एक साधारण क्यूआर कोड के ज़रिए डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं।

इसी दौरान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत के डिजिटल अवसंरचना के मुख्य तंत्र को धीरे-धीरे और निरंतरता से तैयार किया जा रहा है। भारतनेट जैसी परियोजनाओं ने दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक ब्र डबैंड पहुँचाया है, जबकि इंडिया स्टैक ने कागज़-रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित सेवाओं का ढांचा तैयार किया। डिजी-लॉकर ने छात्रों को अपने प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में रखने, और ई-हस्ताक्षर ने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के लिए दूरस्थ प्रमाणीकरण प्रदान किया। डिजी-यात्रा एक अग्रणी पहल है जो चेहरे के पहचान की तकनीक का उपयोग करके निर्बाध, कागज़-रहित और संपर्क-रहित हवाई यात्रा को संभव बनाती है। यह त्वरित चेक-इन, बेहतर यात्री अनुभव और बेहतर हवाई अड्डे की क्षमता में सुधार सुनिश्चित करती है, साथ ही विकेंद्रीकृत पहचान प्रबंधन के माध्यम से डेटा गोपनीयता की सुरक्षा भी करती है। यह भारतीय विमानन के भविष्य की तैयारी और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये मात्र ऐप ही नहीं हैं-ये एक डिजिटल गणराज्य की आधारशिला हैं।

डिजिटल गवर्नेंस ने भी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के शुभारंभ के साथ बड़ी उछाल लगाई है।

सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए डिज़ाइन किए गए, जेम ने 1.6 लाख से अधिक सरकारी क्रेताओं को 22 लाख से अधिक विक्रेताओं से जोड़ा है-जिसमें महिला उद्यमियों और एमएसएमई की बढ़ती संख्या शामिल है। राजस्थान के एक छोटे हस्तशिल्प विक्रेता के लिए, इसका अभिप्राय सरकारी संविदाओं तक पहुंच प्रदान करना था जो पहले अकल्पनीय था।

कृषि क्षेत्र, जिसे प्राय: परिवर्तन के प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता है, ने भी डिजिटल साधनों को अपनाना शुरु कर दिया है। पीएम-किसान जैसे प्लेटफ र्म ने यह सुनिश्चित किया कि आय सहायता किसानों तक सीधे पहुंचे। ई-नैम ने राज्यों की कृषि मंडियों को जोड़ा, जिससे किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सके। डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने उन्हें यह समझने में मदद की कि उन्हें कौन सी फसलें उगानी चाहिए और अपनी भूमि में कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। झारखंड के ग्रामीण-क्षेत्रों में, स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) उनके लिए एक प्रकार से डिजिटल जीवन रेखा बन गए, जो टेली-मेडिसिन से लेकर बैंकिंग और कौशल विकास कार्यक्रमों तक, हर चीज की पेशकश करते हैं।

महामारी भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए एक कठिन परीक्षा थी जिसमें हम बखूबी सफल हुए। स्कूल बंद होने के बावजूद, दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्मों ने यह सुनिश्चित किया कि पढ़ाई अनवरत चलती रहे। लद्दाख और केरल के छात्र भी भारत भर के शिक्षकों द्वारा तैयार की गई शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने अपना आकार लिया, जिससे नागरिकों को एक डिजिटल आईडी के माध्यम से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त हुई और अस्पतालों एवं राज्यों में एक सहज वातावरण बन सका।

वाणिज्य में भी एक शांत क्रांति देखी गई। डीपीआईआईटी की एक पहल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) अब छोटी किराना दुकानों और हथकरघा बुनकरों को बड़ी ई-कामर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना रही है। डिजिटल क मर्स के कार्यों को एकीकृत करके, ओएनडीसी प्रतिस्पर्धा के मैदान को समतल कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोटे व्यवसाय आसानी से लॉजिस्टिक्स, भुगतान और ग्राहक प्रतिक्रिया प्रणालियों तक पहुंच सकें।

नीति आयोग की अभिसरण भूमिका-मंत्रालयों, राज्यों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत को एकजुट करना है-जो सुनिश्चित करता है कि डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं अंतर-संचालनीय, समावेशी और स्केलेबल हों। जैसे-जैसे भारत अपने 5 ट्रिलियन ड लर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, नए आयाम उभर रहे हैं: एआई-सक्षम शासन, विकेन्द्रीकृत वाणिज्य, और बहुभाषी, मोबाइल-प्रथम डिजिटल सेवाएं जो देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं।

लेकिन यह सिर्फ़ एक सरकारी सफलता से जुड़ी कहानी नहीं है। यह एक राष्ट्र की कहानी है-करोड़ें नागरिकों की कहानी है जिन्होंने बदलाव को अपनाया, उद्यमियों की कहानी है जो डिजिटल रेल पर आगे बढ़े, और स्थानीय लीडरों की कहानी है जिन्होंने सेवा वितरण की नई कल्पना की।

भारत का डिजिटल दशक सिर्फ़ तकनीक का नहीं है-यह बदलाव का दशक भी है और यह कहानी का अभी प्रारंभिक चरण ही है।

जीएसटी 2.0: जनता के प्रति जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक

नवनीत कुमार सहगल
अध्यक्ष, प्रसार भारती

सरकार ने इनकम टैक्स में राहत देने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में भी सबसे बड़ा सुधार करते हुए 'जीएसटी 2.0' लागू करने का साहसिक निर्णय लिया है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए यह कदम आसान नहीं होता क्योंकि टैक्स में राहत का सीधा असर राजकोषीय संग्रह पर पड़ता है लेकिन मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार ऐसा करके यह संदेश दिया है कि जनता के हित उसके हर फैसले की धुरी हैं। यह दुर्लभ दृश्य है कि कम समय में दो-दो बड़े टैक्स सुधार लागू किए जाएं। पहले डायरेक्ट टैक्स में राहत और अब इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा बदलाव। यही वह नीति है जिसने मोदी सरकार को आम आदमी के बीच विश्वास का प्रतीक बना दिया है।

विपक्ष की आशंकाएं सच्चाई से कोसों दूर

विपक्ष हमेशा की तरह इस बार भी जनता के हित में लिए गए सरकार के इतने बड़े फैसले भी भ्रम फैला रहा है। विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ दरों का पुनर्गठन किया है और इससे वास्तविक सस्तीकरण नहीं होगा। जबकि सच्चाई यह है कि उपभोक्ता बाजार में पहले ही बदलाव दिखाई दे रहे हैं। दवा कंपनियां नई कीमतें घोषित कर चुकी हैं, बीमा कंपनियां कम प्रीमियम वाली योजनाएं पेश कर रही हैं और उपभोग वस्तुओं के ब्रांड्स ने MRP घटाने की घोषणाएं शुरू कर दी हैं। जहां विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, वहीं वास्तविकता यह है कि यह सुधार जनता की ज़िंदगी को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि टैक्स कलेक्शन की कमी को विकासशील क्षेत्रों और बढ़ी हुई मांग से पूरा किया जाएगा।

आम आदमी के जीवन पर सीधा असर

इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को मिलता दिख रहा है। पहले जहां दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर जहां 12 या 18 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता था अब वे पांच प्रतिशत या 0 टैक्स के दायरे में आ गई हैं। इसका असर रसोई से लेकर दवा की दुकान तक दिखने लगेगा। मोदी सरकार ने खाद्य पदार्थों में सीधी राहत दी है। पैकेज्ड पनीर जैसी चीज़ें अब पहले से सस्ती होंगी। इतना ही नहीं आम आदमी की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी सरकार ने सोचा। जीवनरक्षक दवाएं और कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं जीएसटी मुक्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को भी टैक्स से बाहर करने का फैसला हुआ है। घरेलू उपकरण जैसे टीवी, एसी जैसी रोज़मर्रा की बड़ी ज़रूरतें 28 से घटकर 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। ये कदम केवल राहत का प्रतीक नहीं बल्कि सरकार की उस नीतिगत सोच को भी दर्शाते हैं जिसमें 'जनता की जेब में बचत' को विकास का अहम आधार माना गया है।

उपभोग और मांग में बढ़ोतरी

टैक्स स्लैब घटने का असर सीधे उपभोग पर पड़ना तय है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मांग में तेज़ी आएगी और छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी कंपनियों तक को इसका फायदा मिलेगा। जहां विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ 'इधर से उधर' का खेल है, वहीं आंकड़े बताते हैं कि टैक्स घटने से रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वास्तविक कमी आ रही है। यही वजह है कि बाजारों में पहले ही रौनक लौटने लगी है और त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों में खरीदारी को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।

युवाओं के लिए एक सशक्त अवसर

जीएसटी 2.0 का नया स्ट्रक्चर भारत के युवाओं के लिए एक सशक्त अवसर प्रस्तुत करता है। दरों को सरल बनाकर, अनुपालन प्रक्रिया को सहज बनाकर और बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं पर छूट देकर, यह प्रणाली घरेलू क्रय शक्ति को बढ़ावा देती है। इससे युवाओं की जेब पर सीधा असर पड़ता है ।अब उन्हें रोज़मर्रा की वस्तुएं और सेवाएं पहले से कम कीमतों पर उपलब्ध होंगी। एजुकेशनल मटेरियल पर जीरो टैक्स दर उनके सपनों की उड़ान में मददगार साबित होंगे।

स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को भी लाभ

इस नई व्यवस्था से स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को भी लाभ होगा क्योंकि कम कर दरें और आसान नियम नवाचार को बढ़ावा देंगे। युवा उद्यमियों के लिए यह एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है जिसमें वे अपने विचारों को व्यवसाय में बदल सकते हैं। बीमा जैसी सेवाओं पर छूट उन्हें स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा की ओर प्रोत्साहित करती है।

डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को यह नया जीएसटी ढांचा मजबूत आधार दे रहा है। यह न सिर्फ आज के परिवारों के लिए सुधार है बल्कि उस भारत की नींव है जिसका निर्माण यह युवा पीढ़ी करेगी। वास्तव में जीएसटी 2.0 युवाओं को उपभोक्ता ही नहीं, देश के भविष्य निर्माता बनने की राह पर अग्रसर करता है।

निवेश और उद्योग जगत को बल

जीएसटी 2.0 से सिर्फ ग्राहकों को ही फायदा नहीं होगा, उद्योग जगत के लिए भी यह राहत का पैकेज है। छोटे और मझोले उद्यमों को जटिल टैक्स दरों और कैटेगरी क्लासिफ़िकेशन के बोझ से मुक्ति मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट सरल होगा। अब कंपनियों को इनवॉइस मिलान की जटिलता से नहीं जूझना पड़ेगा, जिससे कारोबारी माहौल आसान होगा। विदेशी निवेशक भी सरल कर संरचना को भारत की आर्थिक क्षमता का मजबूत संकेत मान रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का टैक्स ढांचा अब दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। यह सुधार सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं बल्कि निवेश और रोजगार सृजन का नया द्वार खोलेगा।

महंगाई पर नियंत्रण की रणनीति

मुद्रास्फीति किसी भी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होती है। जीएसटी 2.0 का लक्ष्य केवल उपभोग बढ़ाना नहीं बल्कि महंगाई को नियंत्रित करना भी है। दरअसल, जब ज़रूरी वस्तुएं सस्ती होती हैं तो आम उपभोक्ता की जेब पर दबाव कम होता है और परोक्ष रूप से मुद्रास्फीति की दर घटती है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान हैं कि इस सुधार से महंगाई में 0.5 से 1 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। यह भारत की विकास दर को और स्थिर आधार देगा।

जीडीपी पर प्रभाव के अनुमान

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि जीएसटी 2.0 से आने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी में 0.5 से 1.2 प्रतिशत अंक तक की बढ़ोतरी संभव है। चूंकि उपभोग किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है ऐसे में टैक्स छूट के कारण घरेलू खपत तेज होगी और उद्योग जगत को मांग के नए अवसर मिलेंगे। यह प्रभाव विशेषकर ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में स्पष्ट दिखाई देगा।

शेयर बाज़ार की सकारात्मक प्रतिक्रिया

जीएसटी 2.0 की घोषणा के तुरंत बाद शेयर बाजार ने भी इसे बड़े उत्साह से स्वीकार किया। बीएसई सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक चढ़ा और एनएसई निफ़्टी 50 ने 0.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। ऑटो और कंज़्यूमर गुड्स कंपनियों के शेयरों में 4 से 6 प्रतिशत तक का उछाल देखने को मिला। यह स्पष्ट संकेत है कि उद्योग जगत और निवेशक इस सुधार को दीर्घकालिक लाभकारी मान रहे हैं।

राजकोषीय प्रभाव और सरकार की तैयारी

टैक्स छूट से अल्पकालिक राजस्व में कमी आना स्वाभाविक है। अनुमान है कि इससे सरकार को लगभग 48 हजार करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है लेकिन सरकार आम आदमी के लाभ के प्रति दृढ़ संकल्पित दिखती है। प्रधानमंत्री ने लालकिले से कहा वह कुछ ही दिन में करके दिखा दिया है। जहां तक बात राजस्व घाटे की है तो सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते उपभोग और तेजी से होने वाला आर्थिक प्रवाह इस घाटे को अगले दो ही वर्षो में संतुलित कर देगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 'लोकहित के लिए यदि हमें तात्कालिक घाटा उठाना पड़े तो यह निवेश भविष्य की अर्थव्यवस्था को और मज़बूत बनाएगा।'

सुधार की दिशा में निर्णायक कदम

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट कहा 'यह सुधार सिर्फ़ टैक्स दरों का पुनर्गठन नहीं बल्कि आम जनता की सुविधा, कारोबार में पारदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्णायक पहल है।' जीएसटी 2.0 के तहत कर ढांचे को सरल बनाने के लिए चार दरों को घटाकर दो प्रमुख दरों में समाहित किया गया है। आवश्यक वस्तुओं को 5 प्रतिशत या शून्य कर श्रेणी में लाया गया है जबकि सामान्य उपभोग वस्तुएं 18 प्रतिशत के स्लैब में रखी गई हैं। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए अलग से 40 प्रतिशत का 'डिमेरिट स्लैब' तय किया गया है।

जनता के प्रति जवाबदेही का संदेश

मोदी सरकार के इन निर्णयों का संदेश स्पष्ट है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। यह सिर्फ़ आर्थिक सुधार नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी प्रमाण है। जब पूरी दुनिया में कर वृद्धि की प्रवृत्ति है, भारत ने टैक्स घटाकर यह दिखाया है कि जनता की समृद्धि को ही विकास की असली कुंजी माना गया है।

एक ऐतिहासिक अध्याय

यह कहने में क़तई गुरेज़ नहीं है कि जीएसटी 2.0 केवल कर दरों का पुनर्गठन नहीं बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा में ऐतिहासिक अध्याय है। इसने न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत दी है बल्कि उद्योग, निवेश और दीर्घकालिक विकास की राह भी खोली है। विपक्ष चाहे इसे सतही सुधार बताए लेकिन सच्चाई यही है कि आम आदमी की ज़िंदगी सस्ती और सरल बनाने वाला यह कदम आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को और मज़बूत करेगा। मोदी सरकार ने साबित किया है कि टैक्स नीति केवल राजस्व संग्रह का साधन नहीं बल्कि जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का औज़ार भी है। यही वजह है कि जीएसटी 2.0 को जनता के प्रति जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाएगा।

सी.पी. राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ ली

शिमला। सी.पी. राधाकृष्णन ने भारत के पंद्रहवें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने श्री सी.पी. राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। श्री राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे।

नौकरी की होड़ छोड़कर प्राकृतिक खेती से चुनी आत्मनिर्भरता की राह

नौकरी के पीछे भागने की होड़ छोड़कर, अपने गाँव की मिट्टी से जुड़े रहते हुए खेत-खलिहानों को आय का जरिया बनाने में उच्च शिक्षित युवा अब मिसाल बन रहे हैं। ऐसे ही युवा हैं मंडी जिले के गोहर ब्लॉक के तरौर गाँव के जगदीश चंद। बीएससी फिजिक्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद, जब उनके साथी बेहतर नौकरी की तलाश में शहरों की ओर जा रहे थे, तब जगदीश ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया। उन्होंने रसायन मुक्त खेती और आत्मनिर्भरता की राह चुनी। आज वे न केवल अपनी 20 बीघा जमीन पर एक सफल किसान हैं, बल्कि अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं।

बकौल जगदीश चंद उन्होंने वर्ष 2016-17 में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके बाद खेती-बाड़ी व पशुपालन के पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े। खेती में लगातार बढ़ रहे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को भी उन्होंने महसूस किया। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। बढ़ती लागत और घटती पैदावार ने उन्हें पारंपरिक खेती से मोह भंग करने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान, उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी जुटाई और इस पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया।

शुरूआती दौर आसान नहीं था, चूंकि प्राकृतिक खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे आरम्भ में फसल की पैदावार कम होने का डर रहता है। लेकिन, जगदीश के मजबूत इरादों ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। उन्होंने अपनी 20 बीघा जमीन में से 10 बीघा पर प्राकृतिक खेती शुरू की। आज वे इस जमीन पर पारंपरिक फसलों के अलावा नकदी फसलें मटर, लहसुन और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। फसल की गुणवत्ता और स्वाद रसायनिक खादों से उगी फसलों की तुलना में कहीं बेहतर है, जिससे उन्हें बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं।

जगदीश ने बताया कि वर्ष 2025 में कृषि विभाग की ओर से उन्हें सीआरपी सामुदायिक स्रोत व्यक्ति बनाया है। उन्होंने एक स्वदेशी गाय भी पाल रखी है, जिसके गौमूत्र एवं गोबर का उपयोग वे प्राकृतिक खेती के लिए करते हैं। साथ ही ग्रामीणों को भी इस खेती के आदान उपलब्ध करवाते हैं। इस तरह जगदीश को अपनी खेती को एक व्यावसायिक मॉडल में बदलने का अवसर मिला। राष्ट्रीय प्रा तिक खेती मिशन ने उनके इस सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। इस मिशन के तहत, जगदीश को जैव आदान संसाधन केंद्र खोलने के लिए 25 हजार रुपए की पहली किस्त मिली। उन्होंने इस राशि का उपयोग अपने घर में ही प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक सभी आदान, जैसे जीवामृत, बीजामृत, और घनजीवामृत तैयार करने के लिए किया। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कुल एक लाख रुपए तक अनुदान इसके तहत प्रदान किया जाता है।

जगदीश अब घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला चला रहे हैं, जहां से किसान बहुत ही कम कीमत पर ये जैविक आदान खरीद सकते हैं। इससे जगदीश किसान से एक उद्यमी बन गए हैं। वह सिर्फ अपनी खेती से ही नहीं, बल्कि इन आदानों की बिक्री से भी अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर उन्हें इस पद्धति के बारे में विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं।

खेती के अतिरिक्त उन्होंने दुग्ध उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया है। अपनी गायों के लिए वे रासायनिक खाद रहित चारा तैयार करते हैं और इस तरह से शुद्ध दूध बाजार तक पहुंचाते हैं। उनके अनुसार यह आय का एक स्थाई स्रोत है और परिवार को बेहतर आर्थिक सुरक्षा भी देता है। देसी चारे और जैविक पद्धति से पाला गया उनका पशुधन उनके आत्मनिर्भर जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है।

जिला परियोजना उप निदेशक, डॉ. हितेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 50 प्राकृतिक खेती क्लस्टर बनाए गए हैं और 33 जैव आदान संसाधन केंद्र खोले गए हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों तक प्राकृतिक खेती की विधि को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। इसके लिए 100 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी का चयन किया गया है, जो किसानों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सीआरपी गांवों में जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।

गोहर विकास खंड के खंड तकनीकी प्रबंधक, विजय कुमार के अनुसार, जगदीश चंद जैसे मेहनती युवाओं से प्रेरणा लेकर अन्य किसान भी इस पद्धति को अपना रहे हैं। उनके ब्लॉक में बालड़ी, छपराहण, मिश्राणरी और दिलग टिकरी चार क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 600 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। पूरे गोहर ब्लॉक में अब तक लगभग 2500 किसानों ने प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई। बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को दूर करते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 1,000 टी-मेट्स के पद भरने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने राज्य कैडर के तहत ट्रेनी आधार पर पटवारियों के 645 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के 400 पदों को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने को मंजूरी दी गई।

ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या में वृद्धि लाने के दृष्टिगत 300 जॉब ट्रेनियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इन्हे प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के साथ निर्धारित मासिक वेतन दिया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में 200 चिकित्सा अधिकारियों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में 38 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सचिवालय में 25 स्टेनो-टाइपिस्ट पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

सोलन जिले के परवाणु और धर्मपुर पुलिस थानों में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की उपस्थिति को बढ़ाई जहा सके।

बैठक में पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के संगठनात्मक ढांचे को सुव्यवस्थित करने और पांच नए पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, एक-एक कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पद भरने को भी स्वीकृति दी गई।

लोकायुक्त कार्यालय, हिमाचल प्रदेश में दो जेओए (आईटी) पदों का सृजन कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सात डिनोटिफाइड महाविद्यलायों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के सरप्लस पूल में स्थानांतरित करने को भी अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के

उद्देश्य से 6 सितम्बर, 2025 को जारी उच्च ग्रेड वेतन अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठयक्रम लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में अतिथ्यि उद्योग में मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना शुरू करने को मंजूरी प्रदान की गई ताकि पर्यटन और अतिथ्यि क्षेत्र में प्रदेश के मूल निवासियों को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। इस योजना के अंतर्गत नए होम स्टे के निर्माण अथवा पुराने होम स्टे को स्तरोन्नत करने के उद्देश्य से लिए गए ऋणों पर ब्याज में राहत प्रदान की जाएगी। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में तीन प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रदेश के नौ जिलों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी ताकि मरीजों को घर के निकट ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

मंत्रिमंडल ने मेडिकल ऑफिसर (सामान्य) कैडर को मेडिकल ऑफिसर (सामान्य) और मेडिकल ऑफिसर (विशेषज्ञ) में विभाजित करने मंजूरी दी ताकि प्रदेश के लोगों को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

बैठक में मौजूदा प्रावधानों में संशोधन कर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) का 10 प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक वर्ष 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' को वित्तीय सहायता देने में उपयोग में लाने को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (व्यवसाय एवं प्रक्रिया) नियम 2024 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत, अब उम्मीदवार आवेदन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जैसे वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर एक शपथ पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मंत्रिमंडल ने मॉडल उप-नियम मंजूर किए हैं। यह निर्णय विशेष रूप से हाल के मानसून सीजन के दौरान हुई भारी तबाही को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

बैठक में पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 (1) के तहत अधिकार देने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अनुसार अब वह कांस्टेबल जिसके पास स्नातक की डिग्री है, सात साल की सेवा पूरी कर चुका हो, छः सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण ले चुका हो, निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिस पर कोई विभागीय जांच लंबित नही है, उसे ऐसे मामले की जांच का अधिकार होगा, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान हो।

मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के पांगी तहसील के साच में नई उप-तहसील खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की।

इसी तरह, कांगड़ा जिले की रे उप-तहसील में हटली और मलहंता पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार सर्कल नंगल बनाने का निर्णय भी लिया गया है।

बैठक में कांगड़ा जिले की उप-तहसील चढियार को तहसील का दर्जा देने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमीरपुर जिले के भोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों का पुनर्गठन करने को स्वीकृति दी प्रदान की गई।

कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के हलेड़ स्थित हरसी में जलशक्ति विभाग का नया उप-मंडल खोलने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 के नियम-7 में संशोधन को मंजूरी दी जिससे हिमुडा के पक्ष में भूमि पट्टा अवधि अब 80 वर्ष तक होगी। इससे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित और किफायती दरों पर आवास उपलब्ध हो सकेंगे।

इसके अलावा बैठक में सन्नाया चौलिंग एसोसिएशन, संजौली (शिमला) के पक्ष में सरकारी भूमि पट्टा अवधि को 40 साल के लिए बढ़ाने को स्वीकृति दी गई।

साहसिक पर्यटन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी टेंडेम पायलटों के लिए 31 अगस्त, 2026 को या उससे पहले उड़ानों के दौरान सिमुलेशन पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठयक्रम पूरा करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया, ताकि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में लगे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मंत्रिमंडल ने राज्य के 13 स्थानों पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और सोलर-सीबीजी पावर पोजेक्ट लगाने के लिए पटे पर भूमि देने को मंजूरी प्रदान की।

इसके अलावा, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण को 24 माह बढ़ाकर 3 जून, 2026 तक करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष से भेंट की, आरडीजी जारी रखने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया से भेंट कर हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसमें

अनगिनत बहुमूल्य जानें गई हैं तथा प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। पर्यावरण और बुनियादी ढांचे को हुआ नुकसान अत्यधिक गंभीर है। उन्होंने अवगत करवाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी जुलाई 2025 में यह टिप्पणी की थी कि राजस्व अर्जित करने के लिए पर्यावरण और प्रकृति से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

सुक्खू ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल की राजस्व वृद्धि की अपनी सीमाएं हैं, इसके बावजूद सरकार को संवैधानिक दायित्वों के तहत आवश्यक जन सेवाएं देनी पड़ती हैं। प्रदेश का 67 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वन भूमि होने के कारण राज्य के पास सीमित विकल्प बचे हैं।

मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश जैसे राजस्व घाटे वाले पहाड़ी राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी जारी रहनी चाहिए। राज्य सरकार ने अनुदान की निरंतरता और मात्र मुख्य ज्ञापन और अतिरिक्त ज्ञापन के माध्यम से वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने आरडीजी को कम नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसे राज्य की आय-व्यय की यथार्थपरक स्थिति के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आरडीजी की न्यूनतम राशि 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्त आयोग से जंगल और पर्यावरण से जुड़े मानकों को अधिक महत्त्व देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बर्फ से ढके ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों यानी वृक्ष रेखा से ऊपर के क्षेत्रों को भी घने और मध्य-घने जंगलों में शामिल किया जाए, क्योंकि इनका आपसी संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों द्वारा देश को दी जा रही पारिस्थितिकीय सेवाओं के एवज में हिमाचल प्रदेश ने वार्षिक 50,000 करोड़ रुपये का एक अलग 'ग्रीन फंड' सृजित करने का आग्रह किया है। यह फंड किसी योजना के रूप में या फिर विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत पूंजी निवेश के लिए निर्धारित किया जा सकता है। इस विषय पर वह पहले ही प्रधानमंत्री से चर्चा कर चुके हैं और उन्हें पत्र भी लिख चुके हैं।

उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा तैयार की गई आपदा जोखिम सूचकांक डीआरआई को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपदा की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र की शेष भारत से तुलना नहीं की जा सकती। एक समान प्रारूप में तैयार किया गया सूचकांक भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, जंगल की आग और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जीएलओएफ जैसी आपदाओं को शामिल नहीं करता, जबकि हाल के वर्षों में इन खतरों की आवृत्ति और प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में काफी बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि कम डीआरआई होने के कारण हिमाचल प्रदेश को 15वें वित्तायोग से आपदा राहत के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिले जबकि प्रदेश में आपदाओं को असर कहीं अधिक रहा। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से डीआरआई तैयार करने का आग्रह किया। इसके आधार पर पहाड़ी राज्यों के लिए अलग फंड बनाया जाए और उससे नए डीआरआई के अनुसार राज्यों में वितरित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वां वित्तायोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, इसलिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उठाई गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।

उन्होंने पनगड़िया को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार राज्य में वित्तीय अनुशासन और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री के सलाहकार राम सुभग सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में रॉबोटिक सर्जरी का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सखविंद्र सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ से जिला कांगड़ा में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित रॉबोटिक सर्जरी सुविधा का वर्चुअल माध्यम से शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी ताकि मरीजों को जांच के लिए राज्य के बाहर न जाना पड़े। उन्होंने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग की सीटों को बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन चिकित्सा महाविद्यालयों में भी रॉबोटिक सर्जरी की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 150 से 200 पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात किया जाएगा । इसके अलावा, राज्य में 50 ऑप्रेशन थियेटर

रेडियोग्राफर के पद भी सृजित किए जाएंगे और अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आर.एस. बाली, विधायक संजय रत्तन, किशोरी लाल व आशीष बुटेल, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. मिलाप शर्मा, उद्घाटन समारोह के दौरान टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में उपस्थित थे।

जल शक्ति विभाग को पिछले तीन वर्षों में 4 हजार करोड़ रुपये का नुकसान: मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी. आर. पाटिल से

भेंट कर हाल के दिनों में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रदेश को उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचा है और जल शक्ति विभाग को भी भारी क्षति पहुंची है। पिछले तीन वर्षो के दौरान जल शक्ति विभाग को लगभग 4000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस वर्ष भी विभाग को 1291.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए 1227 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश के सामने आई गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन पीडीएनए के अन्तर्गत धनराशि तुरंत जारी की जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के लिए जलापूर्ति क्षेत्रो लिए स्वीकृत 697 करोड़ रुपये में से अभी तक केवल 100 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग को केवल वर्ष 2023 में ही 2132.70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इससे पुनर्स्थापन कार्यो की प्रगति में बाधा आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर व्यक्तिगत तौर पर विचार करेंगे और हिमाचल प्रदेश के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

उन्होंने पुनर्स्थापन कार्य में तेजी लाने के लिए पीडीएनए के तहत मानदंडों में ढील देने पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने भी मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं के आधार पर केन्द्रीय सहायता जारी करने का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि वह इन दोनों मामलों में प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देंगे।

उप-मुख्यमंत्री ने कमांड एरिया विकास के आधुनिकीकरण से संबंधित योजना को स्वीकृति देने का मामला भी उठाया। जिसे जिला ऊना के हरोली ब्लॉक के विभिन्न क्लस्टरों में लगभग 9778.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया जाना है।

अग्निहोत्री ने पहले से स्वीकृत 11 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने पर बल दिया। उन्होंने अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश में व्यापक पैमाने पर बारिश से नुकसान हुआ है और विभिन्न नदियों के किनारों पर अधिकतम तबाही देखी गई है। इन नदियों व नालों में ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, जल शक्ति विभाग ने केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे से मॉडल अध्ययन कराने के बाद तटीकरण के लिए 1795 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल में लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए इसे जल्द जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे के सामरिक महत्व को देखते हुए ब्यास नदी के तटीकरण के महत्व पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों के लिए नाबार्ड द्वारा विशेष नियम निर्धारण की आवश्यकता पर बल दिया

शिमला/शैल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के उप-प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से ओक ओवर में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदेश सरकार और नाबार्ड के मुख्य

कार्यालय के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करने में निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इससे महत्वपूर्ण मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से ग्राउंड माउंटिड सौर परियोजनाओं को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि आरआईडीएफ के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र मानने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं से पंचायतों को ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने और राज्य सरकार के हरित हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आरआईडीएफ सहायता के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का भी अनुरोध किया।

पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने वार्षिक राज्यवार आवंटन तय करते समय 11 पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मानदंड बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि वन क्षेत्र, हरित पहल और पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान जैसे मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से राज्य योजना विभाग को मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में उपभोक्ताओं तक एक मजबूत और निर्बाध आपूर्ति एवं मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करने का आग्रह भी किया। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने सुधार के दृष्टिगत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के अनुरूप विशेष परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान करने पर बल दिया।

नाबार्ड अधिकारियों ने बताया कि धारा 118 के प्रावधानों के कारण सहकारी समितियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से उनके कार्यक्षेत्र का दायरा सीमित होता है। उन्होंने नई समितियां बनाने के बजाये दूध खरीद का कार्य प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सौंपने और इन समितियों के कम्प्यूटरीकरण में तेजी लाने का भी सुझाव भी दिया।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नाबार्ड के सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और व्यावहारिक सुझावों को राज्य की विकास रणनीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने सतत विकास और ग्रामीण समृद्धि में योगदान देने वाले नवाचारों के प्रति राज्य सरकार की कार्यनीति से अवगत करवाया। नाबार्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के सुझावों पर विचार किया जाएगा और उन्हें भविष्य के दिशा-निर्देशों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

हिमाचल, सहकारिता के क्षेत्र में देश का कर रहा पथ प्रदर्शन:उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न पहलों पर शिमला में हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने हिमाचल प्रदेश को सहकारिता के लिए आदर्श राज्य बताया। उन्होंने कहा कि

विविधता से पूर्ण हिमाचल में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर उन्होंने 121 ई-पैक्स का शुभारंभ भी किया।

बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में सहकारिता की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सहकारिता का जनक है और सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल ने देश को एक नई राह दिखाई है। प्रदेश में सहकारी समितियां बेहतरीन कार्य कर रही हैं। भरोसे का दूसरा नाम सहकारिता है जिसके बल पर प्रदेश की सहकारी समितियों ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान स्थापित की है तथा सफलता की नई बुलदियों को हुआ। हिमाचल में लगभग 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं और प्रदेश की सहकारी समितियां महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रही है। वर्तमान में 2,287 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण वित्तीय समावेशन का कार्य कर रही है। इस दिशा में 6 नई बहुउद्देशीय समितियां गठित की गई हैं।

प्रदेश में 76 समितियां मछली पालन समुदाय, 971 डेयरी समितियां दूध उत्पादन एवं वितरण, 441 समितियां बचत एवं ऋण सुविधा और 386 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद कर रही है। हिमाचल डेयरी क्षेत्र में भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इस क्षेत्र में 561 नई समितियां गठित की गई है।

बैठक में उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सहकारिता को विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र की सहकारी नीतियों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी नीति 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है।

उन्होंने केन्द्रीय राज्य सहकारिता मंत्री से प्रदेश को इस क्षेत्र में उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने तथा हिमफैड और मिल्कफैड का डिजिटाइजेशन करने के लिए सहयोग प्रदान करने को कहा। उन्होंने ऊना जिला के 'हिमकैप्स कॉलेज ऑफ लॉ' को शीघ्र वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

सहकारिता क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए स्थापित की जा रही त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की फीस निर्धारण पर पुन: विचार करने का भी अनुरोध किया।

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सहकारिता क्षेत्र में केंद्र द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने पूर्ण साक्षर राज्य की उपलब्धि हासिल करने पर प्रदेश सरकार को बधाई भी दीं।

बैठक में विभिन्न सहकारी समितियों से आए प्रतिनिधियों ने समितियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

रजिस्ट्रार सहकारी समिति डी. सी. नेगी ने प्रेजेंटेशन दी।

बैठक में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव रमन कुमार, हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव सहकारिता सी. पॉलरासु, कॉपरेटिव बैंकों के एम.डी., हिमफैड, मिल्कफैड, इफ्को के वरिष्ठ अधिकार और विभिन्न सहकारिता समूहों के सदस्य उपस्थित थे।

पर्यावरण संरक्षण में ईको टास्क फोर्स की भूमिका सराहनीय

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए गठित 133 ईको टास्क फोर्स बीते 19

वर्षो से पर्यावरण संरक्षण व पौधरोपण के साथ-साथ आपदा प्रबंधन में भी उल्लेखनीय कार्य किया है।

133-ईको टास्क फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार ने बताया कि स्थापना के बाद प्रदेश में 60.76 लाख पौधे रोपित किये हैं। फोर्स द्वारा 5675 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण के साथ-साथ 4.30 लाख पौधों की क्षमता वाली 11 नर्सरियों की स्थापना भी की गई है। ईको टास्क फोर्स द्वारा तीन अमृत सरोवरों और तालाबों का कायाकल्प किया गया है। पिछले पांच वर्षो में वनों में आग लगने की 43 घटनाओं को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया और मौजूदा 42 परियोजना क्षेत्रों में अग्निशमन लेन की स्थापना तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके 11 चौक डैम भी स्थापित किए गए हैं।

ईको टास्क फोर्स द्वारा वन महोत्सव, एक पेड़ मां के नाम, मेरी माटी मेरा देश, स्वच्छता ही सेवा, विश्व योग दिवस इत्यादि के अवसर पर भी विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। इसके साथ-साथ मृदा संरक्षण, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां निरंतर आयोजित की जाती हैं। आपदा के दौरान बचाव अभियान के दौरान प्रभावित लोगों को आश्रय, भोजन और परिवहन सुविधा प्रदान करने में भी फोर्स की भूमिका सराहनीय है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या पंकज की गिरफ्तारी के बाद मीणा और देशराज की जमानतें रद्द करवा पायेगी सी.बी.आई.?

शिमला/शैल। सी.बी.आई. ने अन्ततः निलंबित ए.एस.आई. पंकज को विमल नेगी मौत प्रकरण में साक्ष्यों को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद इस पर निगाहें लग गयी हैं कि क्या सी.बी.आई. अब हरिकेश मीणा और देशराज की अग्रिम जमानतें रद्द करवा पायेगी। क्योंकि विमल नेगी के परिजनों का मूल आरोप तो मीणा और देशराज के खिलाफ है कि पावर कॉरपोरेशन में इन अधिकारियों के प्रताड़ना पूर्ण व्यवहार ने ही विमल नेगी को मौत तक पहुंचाया है। हरिकेश मीणा को प्रदेश उच्च न्यायालय से और देशराज को सर्वोच्च न्यायालय से अग्रिम जमानतें मिली हुई है। ऐसे में जब तक इन दोनों अधिकारियों से अंतिम पूछताछ नहीं हो जाती है तब तक विमल नेगी की मौत के रहस्य पर से अंतिम पर्दा नहीं उठ पायेगा। यह एक प्रकृति का संयोग है कि इस मामले में ए.एस.आई. पंकज एक केंद्रीय पात्र बन गया है। जिसके गिर्द में यह प्रकरण केंद्रित हो गया है। क्योंकि ए.एस.आई. पंकज वह पुलिस अधिकारी है जो इस मामले में गठित दोनों एस.आई.टी. में से एक में भी आधिकारिक सदस्य नहीं है। यह डी.जी.पी. अतुल वर्मा की उच्च न्यायालय में दायर हुई रिपोर्ट में दर्ज है। बिना किसी भी एस.आई.टी. का सदस्य हुये पंकज उस जगह सबसे पहले पहुंच जाते हैं जहां से विमल नेगी का शव बरामद हुआ था। उस शव की तलाशी लेने और उसमें मिले पेन ड्राइव को फॉरमैट करके उसके रिकॉर्ड को नष्ट करने का आरोप पंकज पर है। जब पंकज पेन ड्राइव को फॉरमैट कर रहा था तब इस दौरान वह किसी से बात भी कर रहा था यह भी अतुल वर्मा की रिपोर्ट में दर्ज है। ऐसे में यह अपने में ही अहम सवाल हो जाता है कि पंकज उस घटना स्थल पर कैसे और किसके निर्देश पर पहुंचा। उसने पेन ड्राइव को फॉरमैट क्यों किया और उस दौरान वह किससे क्या बात कर रहा था। सी.बी.आई. को इन सवालों से पर्दा उठाने के लिये पंकज से सच जानना महत्वपूर्ण हो जाता है।

पावर कॉरपोरेशन जिन विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा था उन में भारी भ्रष्टाचार होने के आरोप है यह भी आरोप है कि स्व. विमल नेगी पर इस भ्रष्टाचार में भागीदार होने का दबाव था और वह इस दबाव के आगे नतमस्तक नहीं हो रहे थे। सी.बी.आई. ने इन परियोजनाओं का सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर उसका विस्तृत अध्ययन करके प्रश्नावली तैयार कर रखी है। जिससे यह सामने आयेगा कि इस कथित भ्रष्टाचार का आकार कितना बड़ा था और उसके लाभार्थी कौन-कौन थे। संभव है कि इस भ्रष्टाचार के छींटे बड़े ऊपर तक आयेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार को हमेशा उसी के आकार का संरक्षण चाहिये होता है।

फिर इसी प्रकरण में एक और बड़ा सवाल है कि स्व. विमल नेगी का शव जिस दिन बरामद हुआ और उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उस रिपोर्ट के मुताबिक नेगी की मौत पोस्टमार्टम से कोई पाचं दिन पहले हो चुकी है लेकिन नेगी के कार्यालय से गायब होने और शव बरामद होने में भी करीब एक सप्ताह का अन्तराल है। इस अन्तराल के दौरान नेगी कहां रहे उनके साथ क्या हुआ यह भी अभी तक बाहर नहीं आया है। ऐसे में जब तक इन सवालों के जवाब अदालत और आम आदमी तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आम आदमी इस जांच से संतुष्ट नहीं होगा और इन सारे सवालों का केन्द्र पंकज बन चुका है।

आपदा पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ज्यादातर समय सदन से ही गायब रहे:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि यह सरकार

न आपदा से बचाव को लेकर ही गंभीर है और न ही राहत कार्यो को प्रभावित तरीके से क्रियान्वित करने को लेकर। प्रदेश में हमेशा एक चलन रहा है कि जब भी मानसून और सर्दी का सीजन आता है तो सरकार द्वारा हाईलेवल मीटिंग करके तैयारियों की समीक्षा की जाती है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों और अपनी तैयारियों का मूल्यांकन किया जाता है। आपदा के जोखिम को न्यूनतम करने, आपात स्थिति से निपटने की पूर्व में ही पूरी योजना बनाने, आपात स्थिति से निपटने के लिए मशीनरी और बजट का प्रावधान किया जाता है। जिससे किसी भी अनहोनी की हालत में राहत और बचाव कार्य तुरन्त शुरू किया जा सके। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में इस बार मानसून के पहले तैयारियों की समीक्षा को लेकर कोई भी हाई लेवल बैठक होने की सूचना नहीं आयी। इसी से ही सरकार की संवेदनशीलता का पता चलता है। इसके बाद जब आपदा से भारी भरकम नुकसान हो गया तो भी सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्यो में युद्ध स्तरीय तेजी लाने के बजाये जुबानी हमले किए गए। आपदा के लिए पूर्व की सरकार को दोषी ठहराया गया। एक सरकार का इससे दुर्भाग्यपूर्ण रवैया नहीं हो सकता है। अब पूरा प्रदेश ही आपदा की चपेट में है तो सरकार के लोग किसे दोष देंगे। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि केंद्र द्वारा दिये गये पैसों को आपदा प्रभावितों तक पहुंचाएं जिससे उन्हें राहत मिल सके।

जयराम ठाकुर ने कहा कि विधान सभा सत्र के दौरान विपक्ष ने आपदा पर चर्चा मांगी और सरकार ने काफी ना नुकूर के बाद उसे स्वीकार किया। चार दिन चर्चा हुई लेकिन दुःख इस बात का है कि उस दौरान मुख्यमंत्री ज्यादातर समय सदन से ही गायब रहे। बिना किसी चुनाव के ही वह बिहार में चुनावी यात्रा निकाल रहे थे। इसी तरह जब चंबा में आपदा आयी तो मणिमहेश यात्रियों के फंसे होने की जानकारी हमने सदन को दी और चर्चा की मांग की। हमने सरकार को सदन के माध्यम से बताया कि कम से कम चंबा में दस हजार से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। उपमुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर हमारी बात का खंडन किया और कहा कि 3300 से कम लोग ही वहां फंसे हुये हैं। दो दिन बाद तक सरकार को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वहां कितने लोग फंसे हैं। वर्तमान सरकार का श्रद्धालुओं को लेकर इस तरीके का प्रबंधन है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि वही नेता तीन दिन बाद सदन और मीडिया के सामने खड़े होकर बताते हैं कि हमने दस हजार से ज्यादा श्रद्धालु बाहर निकाले हैं, मणिमहेश में पन्द्रह हजार से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए थे। जो लोग वहां से बाहर निकाले उन्होंने बताया कि वह पचास-पचास किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आये हैं।

इसी तरह से सरकार द्वारा सदन में कहा गया कि वहां चार-चार हेलीकॉप्टर मणिमहेश में यात्रियों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जब हमने हकीकत पता की तो पता चला वहां पर चार हेलीकॉप्टर वह थे जिन्हें निजी कंपनियां संचालित कर रही थी, जो पहले से ही वहां पर श्रद्धालुओं को लाने ले जाने का काम श्रद्धालुओं के खर्चे पर ही करते थे। आपदा के समय सरकार का उन कंपनियों पर भी नियंत्रण नहीं रहा।

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश

...पृष्ठ 1 का शेष

अग्रिम भुगतान सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-केंद्रित संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन की फिर से समीक्षा करेगी।

प्रधानमंत्री ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास करेगी।